भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निष्पादन का एक अध्ययन

गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], मुकेश कुमार[2]

1–असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश
2–असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश

सारांश

विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत, मुक्त व्यापार व्यवस्था के साथ उभरती प्रतिस्पर्धा का सामना करने और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर समन्वय के लिए, कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं निर्यात को बढ़ावा देने और अपने घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए विवश हैं। इस प्रतिस्पर्धी माहौल में विशेषकर विकासशील देशों में निर्यात में वृद्धि करना विकास के एजेंडे का मुख्य हिस्सा बन गया है और इस विकास एजेंडे को बनाए रखने हेतु सेज एक बेहतर विकल्प साबित हुआ है, क्योंकि सेजों से रोजगार व बुनियादी ढांचे के विकास के साथ अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का अंतर्निहित लाभ माना गया है। भारत भी अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए विकास के सेज एजेंडे का अनुसरण करता है। भारत में फरवरी, 2006 में सेज नियमों की अधिसूचना के बाद 425 सेजों की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए हैं, जिनमें से 358 को अधिसूचित किया जा चुका है। भारत के सेजों में समग्र रूप से 25,60,286 व्यक्तियों को प्रदान किए गए कुल रोजगार में से 24,25,582 वृद्धिशील रोजगार है, जो फरवरी 2006 के बाद सृजित हुए हैं। यह अधोसंरचनात्मक गतिविधियों के लिए विकासकर्ताओं द्वारा सृजित लाखों कार्य–दिवसों के अलावा रोजगार हैं। वर्ष 2020–21 में सेज से भौतिक निर्यात 7,59,524 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जिसमें वर्ष 2019–20 में 7,96,669 करोड़ रुपये की तुलना में उक्त वर्ष के दौरान –4.66 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। पिछले सोलह वर्षों (वर्ष 2005–06 से 2020–21) में निर्यात में समग्र तौर पर 3,225 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2021 तक सेज में कुल निवेश 6,28,565.89 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें सेज अधिनियम 2005 के बाद स्थापित किए गए नए अधिसूचित सेज में 5,92,845.46 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है। प्रस्तुत शोधपत्र में सेज (एसईजेड) के प्रभाव और निष्पादन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः– विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड); रोजगार सृजन, निर्यात निष्पादन, निवेश आकर्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय अनुसंधान एवं विकास; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई); संवृद्धि दर।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का परिचयः– विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज़ उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ से उत्पादन, व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम–कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये विकसित किये जाते हैं। सेज देश के अंदर ही अन्य क्षेत्रों की तुलना में विभिन्न आर्थिक नियमों के तहत रियायत प्राप्त क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। इनको प्राप्त रियायतों में प्रायः निवेश, भूमि अधिग्रहण, व्यापार, कोटा, सीमा शुल्क और श्रम नियम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को कर अवकाश की पेशकश की जाती है, जिसका लाभ उठाकर सेज के अंदर स्थापित कंपनियां वि' व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के उद्देश्य से कम कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार कर सकती हैं। यह देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहते हुए भी वैं`विक एंक्लेव की भांति कार्य करते हैं। इस कारण यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विशेष आकर्षण रखते हैं, क्योंकि यहां व्यापार वृद्धि, रोजगार सृजन, निवेश में वृद्धि और प्रभावी प्रशासन आदि मामलों में व्यावसायिक सुगमता अधिक होती हैं। इसलिए ये व्यावसायिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं।

भारत में सेज के उद्देश्यः– भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैः

1. अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों का सृजन।
2. वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन।
3. घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्द्धन।
4. रोजगार अवसरों का सृजन।
5. अवसंरजना सुविधाओं का विकास।

साहित्य की समीक्षाः–

ड, . एम. आयशा मिलथ और एस. थौसीफ (2016) ने अपने शोध लेख "भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्यात निष्पादन और इसके आर्थिक योगदान" में पाया कि एसईजेड कुल निर्यात मूल्य में एक महत्वपूर्ण राशि का योगदान दे रहा है और कुल निर्यात हर साल रैखिक रूप से आगे बढ़ रहा है। उन्होने वर्ष 2006 से 2016 तक रोजगार और निर्यात प्रदर्शन के संबंध में एसईजेड के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण किया और पाया कि वर्ष 2016 में रोजगार और निर्यात क्षमता का स्तर बहुत कम था।यह भी पाया कि या तो सरकार ने एसईजेड में अधिशेष निवेश किया है या फिर विभिन्न राज्य एसईजेड सुविधाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोनों स्थितियों ने उत्तरोत्तर अवधि में एसईजेड के खराब प्रदर्शन को जन्म दिया है।

एस. एस. भदौरिया (2017) ने अपने शोध लेख "विशेष आर्थिक क्षेत्रः भारतीय अर्थव्यवस्था का एक केस स्टडी" में पाया कि निस्संदेह, एसईजेड की भूमिका सामान्यतः आर्थिक विकास विशेष रूप से औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वित्तीय परिसंपत्तियों, एकल–खिड़की मंजूरी व अन्य क्षेत्रों के सहायता प्रबंधन में मदद करता है जो औद्योगिक विकास की विशेष रूप से लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए पूर्वापेक्षित शर्तें हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की शुरुआत के बाद निवेश, रोजगार और निर्यात में जबरदस्त सुधार हुआ है, जिसके चलते आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति मिली है।

बबीता कुमारी और अन्य (2018) ने अपने शोध लेख "भारत में रोजगार, निवेश और निर्यात सृजन में एसईजेड की भूमिका" में पाया कि सकल निर्यात में कमी के बावजूद कुल निर्यात में सेज का योगदान बढ़ रहा है और एसईजेड का विकास प्रतिशत कुल निर्यात के साथ प्रत्यक्ष आनुपातिकता को दर्शाता है। एसईजेड भारत के आर्थिक विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और रोजगार सृजन व निवेश के आकर्षण में मदद के साथ भारत के निर्यात उत्पादन में योगदान देते हैं।

सन्तोष बी. खलते और ड, . वंदना वी. पिम्पले (2019) ने अपने शोध लेख "भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रदर्शन का अध्ययन" में पाया कि एसईजेड के परिणामस्वरूप रोजगार, निर्यात और निवेश के मामले में देश में सकारात्मक परिणाम आए हैं, हालांकि, एसईजेड के उद्देश्य के अनुरूप रोजगार सृजन, निवेश, निर्यात और आर्थिक विकास हासिल नहीं किया गया है। देश में एसईजेड की उपलब्धियां कुछ विकसित राज्यों में संचालित कुछ एसईजेड तक सीमित हैं।

ड, . पी. गोविंदन (2019) ने अपने शोध लेख "भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रदर्शन का एक अध्ययन" में पाया कि एसईजेड ने निवेश, वृद्धिशील निवेश, रोजगार और वृद्धिशील रोजगार के माध्यम से अतीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा योगदान किए गए कुल भारतीय निर्यात के पच्चीस प्रतिशत से अधिक निर्यात में सकारात्मक वृद्धि भी करता है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सकारात्मक स्थिति मिली है। शीर्ष पांच राज्यों में भारत में कुल एसईजेड का साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहा है।

सूर्य तिवारी (2020) ने अपने शोध लेख "विशेष आर्थिक क्षेत्रः स्थान और भूमि उपयोग" में पाया कि एसईजेड के आकार को मनमाने ढंग से परिभाषित किया गया है, जिस कारण सेजों के पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि पड़ी है। यदि आकार वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया गया होता, तो क्षेत्र की विशिष्टता में कमी नहीं होती। वर्ष 2006 से 2013 तक, कई क्षेत्रों की क्षेत्र आवश्यकता में 50 प्रतिशत की कमी आई थी। जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्र (अस्पतालों को छोड़कर) के संबंध में क्षेत्र आवश्यकता के हालिया वितरण ने आकार तय करने में सैद्धान्तिक कमियों को परिलक्षित किया है। सेज के साथ अप्रयुक्त भूमि सरकार से भूमि के बड़े क्षेत्रों के हस्तांतरण का परिणाम है (जहां सरकार निजी प्रमोटरों की ओर से भूमि का हस्तांतरण या अधिग्रहण करती है)। हालांकि सरकारी एसईजेड के मामले में कोई सतर्कता उपयोग की उम्मीद नहीं है। निजी सेज में अक्षमता के अलावा खाली भूमि भविष्य के दुरुपयोग और भूमि जमाखोरी को भी प्रदर्शित करती है।

अध्ययन के उद्देश्यः– शोध पत्र का उद्देश्य सेज के वैचारिक ढांचे का अध्ययन कर औद्योगिक और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सेज की भूमिका को उजागर करना है। इसलिए हमारे अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. भारत में सेजों की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. सेज के ऐतिहासिक विकास पर अंत–र्ष्टि प्रदान करना।
3. भारत के सकल निवेश के सापेक्ष सेज के निवेश का अध्ययन करना।
4. भारत में सेजों द्वारा रोजगार सृजन का अध्ययन करना।
5. भारत के कुल निर्यात के सापेक्ष सेज के निर्यात का आकलन करना।

अध्ययन की आवश्यकताः– पिछले डेढ़ दशकों से भारत सहित दुनिया के विभिन्न विकासशील देशों में विकास के चालक के रूप में सेजों का महत्व तेजी से बढ़ा है और सेजों को व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के निर्माण, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार, कौशल निर्माण, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, शोध एवं विकास के लिए एक प्रमुख तंत्र के रूप में मान्यता दी गई है। यद्यपि सेज दशकों से अस्तित्व में हैं, लेकिन हाल के वर्षों में व्यापार और वित्तीय बाजारों के वै' वीकरण के कारण दुनिया भर में नए सिरे से

ध्यान आकर्षित किया है। ऐतिहासिक रूप से, सेज आर्थिक विकास में तेजी का परिणाम और कारण दोनों सिद्ध हुए हैं। चूंकि सेज स्थानीय और क्षेत्रीय बुनियादी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो किसी देश के समग्र आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि सभी देशों में सेजों की सफलता एक जैसी नहीं रही है। इसलिए भारतीय संदर्भ में सेजों के निष्पादन और प्रभाव का आकलन करना आवश्यक हो गया है कि क्या उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने में सेजों की भूमिका प्रभावी रही है अथवा नहीं?, निवेशकों को प्रोत्साहन देने में कर रियायतें और लचीले श्रम कानूनों की पेशकश कारगर हुई है अथवा नहीं। या फिर सेज देश में किस हद तक निवेश आकर्षित कर पाए हैं ? कम मजदूरी और लचीले श्रम कानूनों की पेशकश से देश में किस हद तक रोजगार का सृजन हुआ है ?

अनुसंधान अंतरालः– इस अध्ययन में भारत सहित दुनिया भर के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों, शोध अध्ययनों, शोध पत्रिकाओं, कार्य पत्रों, पुस्तकों, नीति दस्तावेजों, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और संगोष्ठियों में संपादित प्रकाशनों की जांच की गई है। इन पृष्ठभूमियों में वर्तमान शोध प्रारंभिक शोधों से कई मायनों में भिन्न है और मौजूदा शोध साहित्य को समृद्ध करने में योगदान करता है।

शोध प्रविधिः–यह अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक आँकड़ों और भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह पर आधारित हैं। इसकी पूर्णता और व्यापकता के लिए विभिन्न स्तरों पर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, अतीत व हालिया प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा की गई। यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्र—ति है, जो विभिन्न मापदंडों में सेजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। सेजों के मामले में वर्ष 2006–07 से 2021–22 की अवधि के आंकड़ों को एकत्र किया गया है। इसके पश्चात आवृत्ति, प्रतिशत, औसत, सारणी और यथावश्यक चित्रात्मक आधार पर कंप्यूटरी–त्त संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण एमएस एक्सेल साफ्टवेयर की मदद से किया गया है।

भारत में सेज का विकासः– निर्यात को बढ़ावा देने में ईपीजेड म, डल की प्रभावशीलता को मान्यता देने वाला भारत एशिया का पहला देश है। देश का पहला ईपीजेड 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। इसके बाद मुंबई में सांताक्रूज़ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1973 में परिचलन में आया। इसके बाद वर्ष 1986 में 4 इपीजेड नोएडा, चेन्नई, कोची और फाल्टा में, 1994 में विशाखापत्तनम में और 1998 में सूरत में स्थापित किए गए थे। एक्जिम नीति के साथ 1 अप्रैल 2000 को घोषित सेज नीति से देश के विभिन्न हिस्सों में सेज की स्थापना के लिए योजना शुरू हुई। जिसके तहत पहले से मौजूद सभी 8 ईपीजेड को सेज में परिवर्तित किया गया। सेज प्रक्रिया को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने हेतु सेज अधिनियम, 2005 को मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया और 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 10 फरवरी, 2006 को सेज नियमों द्वारा समर्थित सेज अधिनियम, 2005 लागू हुआ। यह अधिनियम के तहत लागू सभी रियायतों व अन्य लाभों को सेज क्षेत्रों में उद्यमों को विस्तारित करने की अनुमति देता है। भारत में, एसईजेड को देश की निर्यात क्षमता में वृद्धि, बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास और रोजगार अवसरों के सृजन के माध्यम से विकास चालक के रूप में पेश किया गया है। कुछ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास एसईजेड के विकास के कारण हुआ है।

सारणी–1, भारत में सेजों का विकास क्रम

वर्ष	मार्च, 2008	मार्च, 2009	मार्च, 2010	मार्च, 2011	मार्च, 2012	मार्च, 2013	मार्च, 2014	मार्च, 2015	दिसंबर, 2016	अक्तूबर, 2018	अक्तूबर, 2020	अक्तूबर, 2021
औपचारिक अनुमोदित सेजों की संख्या	453	577	578	585	589	577	571	437	405	421	426	425
अधिसूचित सेजों की संख्या	207	325	353	381	389	389	390	348	329	355	358	358
कार्यशील सेजों की संख्या	19	87	111	133	153	170	190	202	206	231	262	268
सैद्धांतिक अनुमोदित सेजों की संख्या	136	146	149	42	48	49	45	38	32	32	33	34
सेजों में स्वी–त्त इकाइयां	..	2263	2850	3290	3400	3589	3861	4039	4218	5146	5537	5604

सारणी–1, से स्पष्ट है कि सेज अधिनियम के बाद मार्च, 2012 तक अनुमोदित सेजों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है और इसके बाद कमी परिलक्षित हुई है। मार्च, 2008 में अनुमोदित सेजों की संख्या 453 थी, जो बढ़कर मार्च, 2012 में 589 हो गई, फिर घटकर अक्तूबर, 2021 में 425 रह गई। इसी तरह, अधिसूचित सेजों की संख्या में मार्च, 2014 तक निरंतर वृद्धि हुई, जिसके बाद कमी दर्ज हुई। मार्च, 2008 में अधिसूचित सेजों की संख्या 207 थी, जो बढ़कर मार्च, 2014 में 390 हो गई, फिर घटकर अक्तूबर, 2021 में 358 रह गई। देश में कार्यशील सेजों की संख्या मार्च, 2008 में 19 थी, जो

बढ़कर मार्च, 2010 में 111, मार्च, 2015 में 202 और अक्तूबर, 2021 में 268 हो गई। इसी तरह, सेजों में स्वी–त औद्योगिक इकाइयों की संख्या मार्च, 2009 में 2263 से बढ़कर मार्च, 2015 में 4039 और अक्तूबर, 2021 में 5604 हो गई। यद्यपि सेज अधिनियम के बाद कार्यशील सेजों और सेजों में स्वी–त औद्योगिक इकाइयों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है, लेकिन अधिसूचित सेजों के सापेक्ष उनकी क्षमता का संपूर्णता से उपयोग नहीं हुआ है। जैसे मार्च, 2088 में 207 अधिसूचित सेजों के सापेक्ष केवल 19 सेज ही कार्यशील थे अर्थात 188 सेज निष्क्रिय पड़े थे, इसी तरह, मार्च, 2010 में 242, मार्च, 2015 में 146 और अक्तूबर, 2021 में 90 सेज निष्क्रिय पड़े थे। वर्तमान में कुल 268 सेज निर्यात कर रहे हैं। इन में से 162 आईटी/आईटीईएस सेज और 106 मल्टीसेक्टर सेज हैं। सेज में अब तक 5604 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

सेज के ऐतिहासिक विकास पर अंत–ष्टिः– सेज की उत्पत्ति 160 ईसा पूर्व यूरोप में 'फ्री पोट्र्स' और पोर्ट सिटी' की अवधारणा से मानी जा सकती हैं। विकसित दे' ाों ने सेज रणनीति का अनुसरण तब किया जब वे विकसित हो रहे थे। 17वीं और 18वीं ' ाताब्दी में जब घरेलू उद्योग को यूरोप में उच्च प्रशुल्क से आच्छादित किया गया, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीजेड) द्वारा ' ाुल्क मुक्त लाभ प्रदान करके ट्रांसि ापमेंट व्यापार की सुविधा प्रदान की गई। अतः यूरोप एसईजेड बनाने वाला पहला महाद्वीप था, व्यापार और निवेश की सुविधा के लिए आर्थिक क्षेत्र के रूप में एक निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्र पहली बार 1929 में स्पेन में पेश किया गया था। लेकिन पहला आधुनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) 1959 में आयरलैंड में स्थापित किया गया था। ईपीजेड का विचार यूनिडो (यूएनआईडीओ) द्वारा यूरोप, आयरलैंड के एक परिधीय क्षेत्र से लिया गया था। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अधिक प्रभावी तरीके से एसईजेड व्यवस्था का लाभ लिया है। इसने 1930 के द' ाक में अपना एफटीजेड प्रोग्राम ला₩च किया था। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले सेज की स्थापना 1937 में न्यूय, र्क हुई थी। सेज का दूसरा नाम "विदेशी व्यापार क्षेत्रß (एफटीजेड) है। 1942 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्यूर्टोरिको में सेज की स्थापना की, तब से, अन्य देशों ने भी सेज की स्थापना का विचार विस्तारित हुआ है। बाद के वर्षों में, विकास' ाील दे' ाों ने अपनी विकास रणनीति के एक हिस्से के रूप में एसईजेड को अपनाना ' ाुरू किया है और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अभिनव सुविधाओं के साथ प्रयोग किया है। लेकिन विभिन्न देशों में भिन्न–भिन्न नामों से सेज विकसित हुए हैं। सामान्यतः सेज को 6 प्रकारों में विभाजित किया जाता है जिसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, उद्यम क्षेत्र, एकल कारखाने, मुक्त बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं।

सारणी–2, वि' व में सेजों का विकास क्रम

वर्ष	1975	1986	1995	1997	2002	2006	2014	2018
विश्व में सेजों की संख्या	79	176	500	845	3000	3500	4300	5383
भारत में सेजों की संख्या	02	06	07	07	08	19	390	355
सेज देशों की संख्या	25	47	73	93	116	130	138	147
स्रोतः अंकटाड की वि' व निवेश रिपोर्ट, 2019 और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार								

जैसाकि सारणी–2, से स्पष्ट है कि वर्ष 1975 में दुनिया भर के 25 देशों में 79 सेज स्थापित हो चुके थे, जो अगले एक दशक में दो गुना से अधिक बढ़कर 176 हो गए और अगले 9 वर्षों (1995) में करीब तीन गुना बढ़कर सेजों की संख्या 500 हो गई। सेजों की यह संख्या 1997 में दुनिया के 93 देशों में 845 हो चुकी थी, जो अगले पांच सालों में 3.6 गुना बढ़कर 3000 हो गई। सारणी से स्पष्ट है कि 21वीं सदी में सेजों का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। वर्ष 2002 में वि' व के 116 देशों में 3000 सेज थे, जो बढ़कर क्रमशः वर्ष 2006 में 130 देशों में 3500, वर्ष 2014 में 138 देशों में 4300 हो गए थे। वि' व निवे' ा रिपोर्ट, 2019 के अनुसार दुनिया की 147 अर्थव्यवस्थाओं में 5383 एसईजेड मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया भर में 474 सेज विकास की प्रक्रिया में जबकि 507 सेज विकास योजना के अधीन थे।

सारणी–3, विश्व में सेजों का क्षेत्रीय वितरण

वर्ष	उत्तरी अमेरिका	लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन	यूरोप	मध्य पूर्व	एशिया	अफ्रीका	परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाए व अन्यं	वि' व
1997	320	133	81	39	225	47	02	**845**
2018	262	486	105	218	3838	237	237	**5383**
स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और अंकटाड की वि' व निवेश रिपोर्ट, 2019								

सारणी–3, में सेजों के क्षेत्रीय वितरण पर गौर करें तो पिछले 21 वर्षों में वि' व में सेजों की संख्या में 537 प्रतिशत अथवा 6.4 गुना की वृद्धि हुई है, यद्यपि इस अवधि में उत्तरी अमेरिका में सेजों की संख्या में 18 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है, लेकिन यूरोप में 1.3 गुना, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र में 3.7 गुना, अफ्रीका में 5.1 गुना, मध्य पूर्व में 5.6 गुना और एशिया में 17.1 गुना की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर वर्ष 2018 तक स्थापित वि' व के कुल 5383 सेजों में से 374 सेज विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, 4773 सेज विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में और 237 सेज परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं में

थे। फिलहाल तीन चौथाई विकास' ीिल अर्थव्यवस्थाओं ने एसईजेड रणनीति को अपनाया है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से एि ाया में दुनिया के करीब तीन चौथाई एसईजेड स्थापित हैं।

1960 के दशक में जब भारत को —षि की विफलता, बढ़ते आयात बिलों के साथ सीमा संघर्ष सहित कई चुनौतियों के कारण विदेशी मुद्रा की भारी कमी का सामना करना पड़ा, तब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतियों के हिस्से के रूप में, पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड),1965 में स्थापित किया गया था। यह एशिया के किसी देश में स्थापित पहला ईपीजेड था, लेकिन लचर व सीमाबंधित निर्यात और निवेश नीतियों के कारण भारत को इस दिशा में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई। जबकि चीन ने 1978 में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया था जिसको भूस्वामित्व और श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में चीन का उद्देश्य सेज के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करना हो गया है। वर्ष 1975 तक, दुनिया में केवल 79 सेज थे। 1984 के मध्य में तीसरी दुनिया के 35 देशों में 79 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे। 1980 के दशक में चीन के आर्थिक सुधारों के बाद, सेज ने अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की और 1995 तक, दुनिया भर में 500 सेज स्थापित हो चुके थे।

<u>सेज द्वारा सृजित रोजगारः</u>– एसईजेड के विकास के पीछे रोजगार सृजन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है क्योंकि, रोजगार सृजन को किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एसईजेड विकास के लाभ के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा गया है। इस हिसाब से देश के सेजों में फरवरी, 2006 में कार्यरत कार्मिकों की संख्या 1,34,704 थी, जो बढ़कर वर्ष 2020–21 में 23,33,918 कार्मिक और 2021–22 में सितंबर, 2021 तक बढ़कर 25,60,286 कार्मिकों तक पहुंच गई थी। इस तरह देश के सेजों ने पिछले 15 वर्षों में 19 गुना से अधिक रोजगार सृजित किया है। हालांकि, सेजों द्वारा सृजित वास्तविक रोजगार अनुमानित रोजगार से कम रहे हैं।

सारणी–4, भारत में सेज द्वारा सृजित रोजगार का विवरण

वर्ष	सेज द्वारा सृजित वृद्धिशील रोजगार (व्यक्ति)	पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि दर	सेज द्वारा सृजित कुल रोजगार (व्यक्ति)	पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि दर
फरवरी, 2006	134704	--	134704	--
2007-08	201531	49.6	336235	149.6
2008-09	252735	25.4	387439	15.2
2009-10	368907	45.9	503611	29.9
2010-11	541904	46.9	676608	34.4
2011-12	710212	31.1	844916	24.9
2012-13	940200	32.4	1074904	27.2
2013-14	1105141	17.5	1239845	15.3
2014-15	1215367	9.9	1350071	8.9
2015-16	1307612	7.6	1442316	6.8
2016-17	1456677	11.4	1591381	10.3
2017-18	1842512	26.5	1977216	24.2
2018-19	1926351	4.6	2061055	4.2
2019-20	2059768	6.9	2194472	6.5
2020-21	2199214	6.8	2333918	6.4
2021-22*	2425582	10.3	2560286	9.7

स्रोत : वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार *** सितंबर, 2021 तक**

सारणी–4, पर गौर करें तो 2007–08 में वृद्धिशील रोजगार ने 49.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखाई है। इसने 2008–09 में 25.4 प्रतिशत से बढ़कर 2010–11 में लगभग 46.9 प्रतिशत की प्रवृत्ति दिखाई है। इसके बाद वृद्धिशील रोजगार सृजन की वार्षिक वृद्धि दर में कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर वर्ष 2015–16 में 7.6 प्रतिशत रह गई। यद्यपि वर्ष 2016–17 और 2017–18 में क्रमशः 11.4 और 26.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई लेकिन अगले ही वर्ष 2018–19 में यह घटकर अपने न्यूनतम स्तर 4.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। अतः कार्यशील सेजों की संख्या में निरंतर वृद्धि के बावजूद सेजों द्वारा सृजित वृद्धिशील रोजगार सृजन की वृद्धि दर संतोषजनक नहीं रही है।

सारणी–5, भारत में सेज के तहत रोजगार का विवरण

(रोजगार हजार में जबकि कोष्ठक में रोजगार का प्रतिशत)

रोजगार	2006	2008-09	2010-11	2012-13	2014-15	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
केंद्र सरकार के सेज	122.24 (90.8)	196.92 (50.8)	210.43 (31.1)	219.40 (20.4)	211.35 (15.7)	227.57 (14.3)	260.99 (13.2)	228.04 (11.1)	227.12 (10.3)	189.05 (8.1)	193.59 (7.6)
2006 से पूर्व स्थापित राज्यीय /निजी सेज	12.47 (9.2)	55.89 (14.4)	66.30 (9.8)	89.94 (8.4)	75.68 (5.6)	82.75 (5.2)	106.77 (5.4)	103.05 (5.0)	106.16 (4.8)	100.36 (4.3)	109.75 (4.3)
कुल अधिसूचित सेज	0.0	134.63 (34.7)	400.14 (59.1)	765.57 (71.2)	1063.05 (78.7)	1281.06 (80.5)	1609.45 (81.4)	1729.97 (83.9)	1861.20 (84.8)	2044.51 (87.6)	2256.95 (88.1)
कुल रोजगार	**134.70 (100)**	**387.44 (100)**	**676.61 (100)**	**1074.90 (100)**	**1350.07 (100)**	**1591.38 (100)**	**1977.22 (100)**	**2061.05 (100)**	**2194.47 (100)**	**2333.92 (100)**	**2560.29 (100)**

स्रोत : वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार * सितंबर, 2021 तक

सेजों के स्वामित्व के अनुसार कुल रोजगार सृजन पर सारणी–5, में गौर करें तो 2006 में सबसे ज्यादा रोजगार केंद्र सरकार के सेजों में 122.24 हजार कार्मिक थे, जो सेजों के कुल रोजगार का लगभग 90.75 प्रतिशत था। जबकि 2006 से पूर्व स्थापित राज्यीय/निजी सेजों में कुल रोजगार का केवल 9.2 प्रतिशत हिस्सा था। इसके बाद सेज अधिनियम के तहत कुल अधिसूचित सेजों में रोजगार सृजन बढ़ा है, जबकि केंद्र सरकार के सेजों और 2006 से पूर्व स्थापित राज्यीय/निजी सेजों में कुल रोजगार का हिस्सा घटा है। वर्ष 2008–09 में कुल रोजगार सृजन में अधिसूचित सेजों का हिस्सा 29.2 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2014–15 में 78.7 प्रतिशत, 2020–21 में 87.6 प्रतिशत और 2021–22 में सितंबर, 2021 तक बढ़कर 88.1 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में केंद्र सरकार के सेजों का हिस्सा 50.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 15.7 प्रतिशत, 2020–21 में 8.1 प्रतिशत और 2021–22 में सितंबर, 2021 तक घटकर 7.6 प्रतिशत हो गया। जबकि 2006 से पूर्व स्थापित राज्यीय/निजी सेजों का हिस्सा 14.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 5.6 प्रतिशत और 2020–21 में 4.3 प्रतिशत रह गया। कुल मिलाकर कार्यशील सेजों की संख्या में वृद्धि के साथ कुल रोजगार सृजन में अधिसूचित सेजों का हिस्सा निरंतर बढ़ने के बावजूद सेजों द्वारा सृजित वास्तविक रोजगार अनुमानित रोजगार से कम रहे हैं।

सेज द्वारा निर्यातः– कुल 16 पूर्ण वित्तीय वर्ष (2005–06 से 2020–21 तक) के परिणाम बताते हैं कि भारत के कुल निर्यात में 12 साल सकारात्मक और शेष 4 साल नकारात्मक वृद्धि दर वाले रहे हैं। जबकि इसी अवधि में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्यात के परिणामों से पता चलता है कि पिछले 16 वित्तीय वर्षों में से 14 साल सकारात्मक और दो साल नकारात्मक वृद्धि दर वाले रहे हैं। जैसाकि सारणी–6 से स्पष्ट हो रहा है।

सारणी–6, भारत में सेज द्वारा निर्यात का विवरण

वर्ष	सेज द्वारा निर्यात (करोड़ रु में)	सेज द्वारा निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर	देश का कुल निर्यात (करोड़ रु में)	देश के कुल निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर	देश के कुल निर्यात में सेज निर्यात का हिस्सा
2005-06	22840	--	456418	21.6	5.0
2006-07	34615	51.5	571779	25.3	6.1
2007-08	66638	92.5	655864	14.7	10.2
2008-09	99689	49.6	840755	28.2	11.9
2009-10	220711	121.4	845534	0.6	26.1
2010-11	315686	43.1	1136964	34.5	27.8
2011-12	364478	15.4	1465959	28.9	24.9
2012-13	476159	30.6	1634318	11.5	29.1
2013-14	494077	3.8	1905011	16.6	25.9
2014-15	463770	-6.1	1896348	-0.5	24.5
2015-16	467337	0.8	1716378	-9.5	27.2
2016-17	523637	12.1	1849434	7.8	28.3
2017-18	581033	11.0	1956515	5.8	29.7
2018-19	701179	21.0	2307726	18.0	30.4
2019-20	796669	13.6	2219854	-3.8	35.9
2020-21	759524	-4.7	2159043	-2.7	35.2
2021-22*	448247	28.3	2238821	49.3	20.0

स्रोत : वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आर्थिक सर्वेक्षण, 2021–22, भारत सरकार

* वर्ष 2021–22 के लिए कुल निर्यात व वृद्धि दर अप्रैल से दिसंबर तक पिछले वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष जबकि सेज द्वारा निर्यात व वृद्धि दर अप्रैल से सितंबर तक पिछले वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष दी गई है।

सारणी–6 में 16 वर्षों के विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्यात और भारत का कुल निर्यात दर्शाया गया है । भारत में कुल निर्यात की मात्रा 2005–06 में 4,56,418 करोड़ रु. से बढ़कर 2018–19 में 23,07,726 करोड़ रु. हो गई है। हालांकि 2014–15 और 2015–16 के दौरान निर्यात की मात्रा में गिरावट आई, लेकिन इसमें तेजी आई और बाद के वर्षों में 2.72 गुना की वृद्धि प्राप्त हुई। तीन वर्षों की सतत वृद्धि के बाद पुनः 2019–20 और 2020–21 के दौरान निर्यात की मात्रा में गिरावट आई। इस तरह अध्ययन अवधि के 16 वर्षों के दौरान 2010–11 में सर्वाधिक वृद्धि दर 34.5 प्रतिशत, जबकि वर्ष 2015–16 में न्यूनतम या ऋणात्मक वृद्धि दर –9.5 प्रतिशत देखी गई है।

पिछले 16 वर्षों के दौरान भारत द्वारा किए गए सेज निर्यात वर्ष 2014–15 और 2020–21 को छोड़कर साल दर साल बढ़ रहे हैं। सेज का निर्यात 2005–06 में 22,840 करोड़ रु. से बढ़कर 2019–20 में 7,96,669 करोड़ रु. हो गया है, जिसका अर्थ है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान इसमें 34.8 गुना की वृद्धि हुई है। यदि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत देखें तो यह 121.4 प्रतिशत से –6.1 प्रतिशत के बीच रहा है। वर्ष 2009–10 में सर्वाधिक वृद्धि दर 121.4 प्रतिशत प्रतिशत जबकि वर्ष 2014–15 में –6.1 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है।

दस वर्षों (2009–10 से 2018–19) की अवधि के दौरान देश द्वारा किए गए सेज निर्यात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 12.15 प्रतिशत थी जो एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति है। यह देखा गया है कि चार वर्षों की वृद्धि दर सीएजीआर से अधिक थी और शेष पांच वर्षों की वृद्धि दर सीएजीआर से कम थी। जबकि देश के कुल निर्यात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.56 प्रतिशत थी जिसमें से पांच वर्षों की वृद्धि दर सीएजीआर से अधिक थी और चार वर्षों की वृद्धि दर सीएजीआर से कम थी। इस तरह भारत के कुल निर्यात की सीएजीआर (10.56 प्रतिशत) के सापेक्ष सेज निर्यात की सीएजीआर (12.15 प्रतिशत) अधिक रही है।

अध्ययन अवधि में सेज द्वारा निर्यात की प्रवृत्ति कुल निर्यात की तुलना में काफी सकारात्मक रही है। भारत के कुल निर्यात में सेज निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2005–06 में 5.0 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2009–10 में 26.10 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 2019–20 और 2020–21 में 35.9 और 35.2 प्रतिशत हो गई। कुल मिलाकर भारत के कुल निर्यात में सेज निर्यात की हिस्सेदारी में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है।

सेज द्वारा आकर्षित निवेशः– भारत के सेजों में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमन्य है। जो विदेशी और एनआरआई निवेशकों में भारतीय सेजों में अपना पैसा निवेश करने का आकर्षण पैदा करते हैं। फरवरी, 2006 में सेज अधिनियम लागू होने के बाद से सेज में वृद्धिशील निवेश 624530.38 करोड़ रुपये हुआ है। सेज में निवेश फरवरी, 2006 में 4035.51 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,28,565.89 करोड़ रुपये हो गया जिसका अर्थ है कि पिछले 17 वर्षों के दौरान इसमें 155.7 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरह देश के सेजों में निवेश ने समय के साथ सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। हालांकि, घरेलू और वैश्विक बाजार में कई प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण इसकी वृद्धि दर एक समान नहीं रही है।

सारणी–7, भारत में सेज पर निवेश का विवरण

वर्ष	सेज द्वारा वृद्धिशील निवेश (करोड़ रु में)	सेज द्वारा कुल निवेश (करोड़ रु में)	पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि दर	देश का सकल निवेश (करोड़ रु में)	देश के कुल निवेश में सेज का हिस्सा
फरवरी, 2006	4035.5	4035.5	--	1322989	0.3
2007-08	73173.9	77209.5	1813.3	1917072	4.0
2008-09	104867.5	108903.0	41.0	2115027	5.1
2009-10	144453.1	148488.6	36.3	2473478	6.0
2010-11	198774.0	202809.5	36.6	3037520	6.7
2011-12	197839.3	201874.8	-0.5	3403008	5.9
2012-13	232681.6	236716.7	17.3	3847122	6.2
2013-14	284441.5	288476.5	21.9	3794135	7.6
2014-15	334758.9	338794.5	17.4	4179779	8.1
2015-16	369418.4	373454.0	10.2	4422659	8.4
2016-17	402654.1	406689.7	8.9	4918077	8.3
2017-18	470881.9	474917.4	16.8	5791573	8.2
2018-19	503608.5	507644.0	6.9	6172623	8.2
2019-20	517595.9	521631.4	2.8	6551251	7.9
2020-21	591083.8	595119.3	14.1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2021-22*	624530.4	628565.9	5.6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्रोतः वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आर्थिक सर्वेक्षण, 2021–22, भारत सरकार * अक्तूबर, 2021 तक

सेज अधिनियम 2005 के बाद सेज नीति में नरमी के कारण सेज के सभी क्षेत्रों में निवेश लगातार बढ़ा है। सारणी–7, से स्पष्ट है कि 2006 में कुल निवेश 4035.51 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021–22 तक यह 628565.89 करोड़

रुपए हो गया। 2006 और 2007 के बीच कुल निवेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि यह भारत में एसईजेड के विकास का प्रारंभिक चरण था। 2010–11 तक कुल निवेश में निरंतर वृद्धि होती रही, लेकिन 2011–12 में कुल निवेश में –0.5 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके बाद 2014 तक कुल निवेश में फिर से वृद्धि हुई है, लेकिन 2014 में सेज नियम में बदलाव के कारण 2015 में फिर से गिरावट आई है। वर्ष 2015–16 से पुनः कुल निवेश में वृद्धि शुरू हुई और यह 2015–16 में 373454 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 628565.89 करोड़ रुपए हो गया।

सारणी–8, भारत में सेज के तहत निवेश का विवरण

(निवेश अरब रु में जबकि कोष्ठक में निवेश का प्रतिशत)

निवेश	2006	2008-09	2010-11	2012-13	2014-15	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
केंद्र सरकार के सेज	22.79 (56.5)	48.71 (4.5)	104.53 (5.2)	119.19 (5.0)	111.80 (3.3)	158.94 (4.0)	175.72 (3.7)	186.77 (3.7)	194.41 (3.7)	208.72 (3.5)	220.92 (3.5)
2006 से पूर्व स्थापित राज्यीय/निजी सेज	17.56 (43.5)	55.34 (5.1)	77.16 (3.8)	87.49 (3.7)	101.64 (3.0)	117.80 (3.0)	128.23 (2.7)	132.74 (2.6)	134.33 (2.6)	144.37 (2.4)	136.29 (2.2)
कुल अधिसूचित सेज	0.0	984.98 (90.4)	1846.41 (91.0)	2160.47 (91.3)	3174.50 (93.7)	3790.16 (93.0)	4445.23 (93.6)	4756.93 (93.7)	4887.57 (93.7)	5598.11 (94.1)	5928.45 (94.3)
कुल निवेश	**40.36 (100)**	**1089.03 (100)**	**2028.09 (100)**	**2367.17 (100)**	**3387.95 (100)**	**4066.89 (100)**	**4749.17 (100)**	**5076.44 (100)**	**5216.31 (100)**	**5951.19 (100)**	**6285.66 (100)**

स्रोत : वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार * अक्तूबर, 2021 तक

केंद्र सरकार के सेजों में निरपेक्ष निवेश कुछ विचलनों के साथ लगातार बढ़ा है, यह वर्ष 2006 में 2279.2 करोड़ से बढकर 2021–22 में 22091.68 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2013–14 में –4.78 प्रतिशत की कमी को छोड़कर 2015–16 से 2019–20 के बीच निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। जबकि कुल सेजों के सापेक्ष केंद्र सरकार के सेजों का हिस्सा इस अवधि में 56.5 से घटकर 3.5 प्रतिशत रह गया है। इसी तरह, 2006 से पूर्व स्थापित राज्यीय/निजी सेजों का हिस्सा 43. 5 से घटकर 2.2 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत सेज अधिनियम से तहत स्थापित कुल सेजों का हिस्सा वर्ष 2007–08 में 89.8 से बढ़कर 94.3 प्रतिशत हो गया है। इस तरह, वर्ष 2006 तक केंद्र सरकार के सेज सबसे अधिक निवेश आकर्षित करते थे, जो कुल निवेश का लगभग 56.5 प्रतिशत तक था और शेष निवेश राज्य/निजी एसईजेड के तहत था, क्योंकि उस समय सेजों की अधिसूचना नहीं थी। समय बीतने के साथ नियमों में संशोधन और अर्थव्यवस्था के व्यवहार में बदलाव के कारण अधिसूचित सेजों के निवेश हिस्से में क्रमिक वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर पिछले 11 वर्षों (2006–07 से 2016–17) की अवधि के दौरान देश के सेजों द्वारा आकर्षित निवेश की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 52.97 प्रतिशत थी जो एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति है। यह देखा गया है कि समग्र सीएजीआर 52.97 प्रतिशत की तुलना में केंद्र सरकार, 2006 से पूर्व स्थापित राज्यीय/निजी सेजों और सेज अधिनियम से तहत स्थापित कुल सेजों में आकर्षित निवेश की सीएजीआर क्रमशः 19, 19 और 19.3 प्रतिशत रही है।

सारणी–7, से स्पष्ट है कि देश के सेजों में निवेश की प्रवृत्ति कुल निवेश के सापेक्ष सकारात्मक रही है। भारत के कुल निवेश में सेज निवेश की हिस्सेदारी फरवरी, 2006 में 0.3 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2008–09 में 5.1 प्रतिशत हो गई और इसके बाद यह हिस्सेदारी हमें' ाा पांच से अधिक ही रही है। यदि वर्ष 2009–10 से 2019–20 तक के 11 वर्षों के औसत को देखें तो देश के कुल निवेश में सेज निवेश की हिस्सेदारी औसतन 7.4 प्रतिशत रही है। कुल मिलाकर भारत के कुल निवेश में सेज निवेश की हिस्सेदारी हमेशा सकारात्मक रही है।

निष्कर्ष एवं सुझावः– प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश के अधिसूचित सेजों के सापेक्ष कार्यशील सेजों की संख्या कम होने के बावजूद निर्यात, निवेश और रोजागार सृजन की –ष्टि से सेजों का निष्पादन सकारात्मक रहा है। रोजगार सृजन को किसी भी देश में एसईजेड के विकास के लाभ के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा गया है। इस –ष्टि से भारत में सेज से 2006 में 134.70 हजार लोगों से बढ़कर वर्तमान में 2560. 29 हजार लोग राष्ट्रीय स्तर पर में काम कर रहे हैं। इसी तरह, देश के कुल निर्यात में कमी के बावजूद कुल निर्यात में सेज का योगदान बढ़ रहा है। सेज का विकास प्रतिशत कुल निर्यात के साथ प्रत्यक्ष आनुपातिकता को दर्शाता है। 2006 में कुल निर्यात में सेज निर्यात का योगदान केवल 5 प्रतिशत था जो 2013 में 29 प्रतिशत तक पहुंच गया और यह कुछ विचलनों के साथ बढ़कर 2019–20 में 35.9 प्रतिशत हो गया। अतः देश के कुल निर्यात में सेज निर्यात की हिस्सेदारी में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। सेज में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वजह से घरेलू के साथ विदेशी और एनआरआई निवेशक भी भारतीय सेजों में अपना पैसा निवेश करने में रुचि प्रस्तुत करते रहे हैं। सेज अधिनियम, 2005 के बाद सेज नीति में नरमी के कारण सेज के सभी क्षेत्रों में निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। 2006 में कुल निवेश सिर्फ 4035.51 करोड़ था, जो अक्तूबर, 2021 तक बढ़कर 628565.89 करोड़ रुपए हो गया।

यद्यपि सेजों ने रोजगार, निर्यात और निवेश के मामले में सकारात्मक परिणाम दिए हैं, हालांकि, अनुमान और उद्देश्य के अनुरूप निष्पादन प्रस्तुत नहीं किया है। सेजों के माध्यम से विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए अभी पर्याप्त गुंजाइश है, क्योंकि देश में सेजों की उपलब्धियां कुछ विकसित राज्यों में संचालित कुछ सेजों के योगदान तक

सीमित है। सेजों के सभी क्षेत्रों द्वारा इच्छित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की उपलब्धि में कमी को ध्यान में रखते हुए, सेजों के बेहतर परिणाम के लिए नीतिगत ढांचे और इनके कार्यान्वयन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो क्षेत्रवार वितरण की –ष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, दूरसंचार उपकरण जैसे क्षेत्रों ने भारत के सेजों पर निवेश, निर्यात और रोजगार निष्पादन का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित किया है। दूसरा, शीर्ष पांच राज्यों में भारत के कुल सेजों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। इसलिए शीर्ष पांच राज्यों व क्षेत्रों के अलावा अन्य राज्यों व क्षेत्रों में नए सेज स्थापित करने के लिए विभिन्न मौद्रिक और गैर–मौद्रिक स्टार्टअप, सब्सिडी सहयोग और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर अवकाश देने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

कुल मिलाकर सेज भारत के आर्थिक विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि रोजगार सृजन, निवेश के आकर्षण और भारत के निर्यात उत्पादन में सेजों के योगदान से स्पष्ट हो रहा है। साथ ही इनके निष्पादन को बहुआयामी और समावेशी बनाने के लिए सरकार को गैर–परिचालन और अंडरपरफ, Émग सेजों के विकास में बाधा डालने वाले कारकों की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।

स्रोत संदर्भः–

[1] http://sezindia.nic.in/hi/cms/aboutintroduction-hi.php
[2] https://commerce.gov.in/hi/about-us/subordinate-offices/offices-of-development-commissioners-of-special-economic-zones-sezs
[3] https://commerce.gov.in/hi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Commerce-Annual-Report_2021-22-Hindi.
[4] http://sezindia.nic.in/upload/Factsheet
[5] https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2014/Union_Hindi_INDT_Report_21_2014
[6] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/SSLAK160909.pdf
[7] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007997/lang--en/index.htm
[8] https://unctad.org/system/files/official-document/WIR2019_CH4.pdf
[9] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1703791
[10] http://164.100.47.193/Refinput/New_Reference_Notes/English/SEZ_in_India.pdf
[11] https://www.phdcci.in/wp-content/uploads/2018/11/Research-Study-on-Special-Economic-Zones-in-India-April-2017
[12] https://openknowledge.worldbank.org/Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Directions

Mukesh Kumar, **Assistant Professor (Economics),** Department of Economics, Goswami Tulsidas PG College, Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh-210205	**Gajendra Singh 'Madhusudan'** **Assistant Professor (Economics),** Department of Economics, Goswami Tulsidas PG College, Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh-210205